भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1445
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026
असम के विश्वनाथ जिले में केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव

†1445. **श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:**
श्री रंजीत दत्ता:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के प्रोद्दुटूर-वाईएसआर कडप्पा जिले में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि असम के विश्वनाथ जिले की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और वहां बड़ी संख्या में स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारी तैनात हैं लेकिन जिले में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जिससे ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;
(ग) क्या सरकार का चालू या आगामी वित्त वर्ष के दौरान असम के विश्वनाथ जिले में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हाँ, तो इसकी मंजूरी और स्थापना के लिए संभावित समय क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत् प्रक्रिया है। केवि पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों सहित रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं जिनमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के

मानदंडों के अनुसार एक नया केवि स्थापित करने के लिए निःशुल्क अपेक्षित भूमि और उपयुक्त किराया-मुक्त अस्थायी आवास को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल होती है। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में 38 केवि कार्यात्मक हैं और असम राज्य में 57 केवि कार्यात्मक हैं।

केविसं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रोद्दुटूर, वाईएसआर कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश और विश्वनाथ जिला, असम में नए केवि खोलने के लिए संबंधित राज्य सरकार / जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

******